



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2017/ पौष 27, 1938

No. 17]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2017/PAUSA 27, 1938

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2017

वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (एफओओ) आधार पर स्थापित विद्युत स्टेशनों से मध्यावधि विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए दिशा-निर्देश

सं. 23/17/2013-आरएंडआर(खंड-V).—जबकि केंद्र सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार विद्युत उत्पादन के सुव्यवस्थित विकास के लिए एक सक्षम नीति और विनियामक वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है;

जबकि प्रतिस्पर्धात्मक और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्युत की अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विद्युत विनियामक आयोगों और वितरण लाइसेंसधारकों के लिए आवश्यक है;

जबकि केंद्र सरकार ने विभिन्न पणधारकों और विशेषज्ञों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, उन विद्युत उत्पादकों से, जो मध्यावधि के लिए "वित्त, स्वामित्व और प्रचालन" ("एफओओ") के आधार पर अथवा विद्युत उत्पादकों के साथ बैंक-टू-बैंक प्रबंध रखने वाले व्यापारियों/डिस्कॉम से ताप विद्युत स्टेशनों का निर्माण और/अथवा प्रचालन करने के लिए सहमत हों, वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए एक आदर्श संविदात्मक ढांचा तैयार किया है;

जबकि केंद्र सरकार ने अपने पत्र सं. 23/17/2013-आरएंडआर (खंड-II) दिनांक 29 जनवरी, 2014, के माध्यम से मॉडल दस्तावेज जारी किए हैं जिसमें मॉडल पात्रता अनुरोध ("एमआरएफक्यू") मॉडल प्रस्ताव अनुरोध ("एमआरएफपी") और मॉडल विद्युत अधिप्राप्ति करार ("एमएपीपी") (संयुक्त रूप से, "मानक बोली दस्तावेज") शामिल हैं जिसे बिजली की अधिप्राप्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा अपनाया जाना है।

उपर्युक्त के आधार पर, भारत सरकार ने 10 फरवरी, 2014 की संकल्प सं. 23/17/2013-आरएंडआर (खंड-II) के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए थे जिन्हें आगे 20 अगस्त, 2015 के संकल्प के तहत संशोधित किया गया था।

जबकि केंद्र सरकार ने, दिनांक 16 जनवरी, 2017 के पत्र सं.23/17/2013-आरएंडआर(खंड-V)के तहत सिंगल दस्तावेज "मानक बोली दस्तावेज" जारी किया है जिसमें दोनों पात्रता हेतु मॉडल अनुरोध ("**एमआरएफक्यू**") तथा प्रस्ताव हेतु मॉडल अनुरोध ("**एमआरएफपी**"), तथा विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु मॉडल करार ("**एमएपीपी**") शामिल है (संयुक्त रूप से, "**मानक बोली दस्तावेज**") तथा एमएपीपी को मॉडल बोली दस्तावेज के रूप में संदर्भित किया गया है) और जो वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के प्रापण के लिए एफओओ आधार पर निर्मित और/अथवा प्रचालित विद्युत उत्पादन स्टेशनों से न्यूनतम प्रशुल्क के ऑफर पर आधारित वैद्युत मंच (डीईईपी ई-बिडिंग पोर्टल) के माध्यम से खुली एवं पारदर्शी प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा विद्युत उत्पादकों/व्यापारियों/डिस्कॉमों से प्राप्त किए जाने हैं। बिडिंग पोर्टल हेतु लिंक www.mstcecommerce.com, है तथा यह विद्युत मंत्रालय (www.powermin.nic.in) और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (www.pfcclindia.com) पर भी उपलब्ध है।

इसलिए अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इन दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करती हैं जिन्हें वित्त, स्वामित्व, प्रचालन (एफओओ) आधार पर स्थापित विद्युत स्टेशनों से मध्यावधि के लिए विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु दिशा-निर्देश ("**दिशानिर्देश**") के रूप में जाना जाएगा। ये दिशा-निर्देश शासकीय राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन रहते हुए इसकी तारीख से प्रभावी होंगे:

1. उपरोक्त मॉडल बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तें, संदर्भ द्वारा इन दिशा-निर्देशों का भाग होगी और इन्हें इसी रूप में माना जाएगा।
2. इन दिशा-निर्देशों का लागू किया जाना उन परियोजनाओं तक ही सीमित होगा जहां से एक और पांच वर्षों की अवधि के लिए पारस्परिक सहमति से आरंभिक करार अवधि 25% तक अथवा एक वर्ष, जो भी कम हो, के लिए इस अवधि को बढ़ाने के प्रावधान सहित विद्युत की अधिप्राप्ति के करार के अनुसार विद्युत अधिप्राप्ति की जाती है।
3. मॉडल बोली दस्तावेजों को शामिल करते हुए इन दिशा-निर्देशों के आधार पर विद्युत बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित प्रशुल्क अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसरण में उपयुक्त आयोग द्वारा अपनाया जाएगा।
4. वितरण लाइसेंसियों द्वारा मॉडल बोली दस्तावेजों से कोई विचलन उपयुक्त आयोग के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा। बशर्ते यह कि मॉडल बोली दस्तावेजों में अभिव्यक्त रूप से अनुमति दिए गए किसी परियोजना विशेष संशोधनों का अर्थ मॉडल बोली दस्तावेजों से विचलन के रूप में नहीं लगाया जाएगा।
5. नई कोयला ब्लॉक नीलामी नीति को ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के संकल्प सं. 23/9/2015-आरएंडआर के माध्यम से डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (डीबीएफओओ) आधार पर स्थापित ताप विद्युत केंद्रों से विद्युत की अधिप्राप्ति के दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन **यथाआवश्यक परिवर्तनों** सहित, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (एफओओ) आधार पर स्थापित विद्युत स्टेशनों से मध्यकालिक अवधि के लिए विद्युत की अधिप्राप्ति पर भी लागू होंगे।

वितरण लाइसेंसियों द्वारा, 29 जनवरी, 2014 को जारी मानक बोली दस्तावेजों सहित विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा प्रशुल्क के निर्धारण हेतु 10 फरवरी, 2014 को जारी व 20 अगस्त, 2015 को यथासंशोधित दिशा-निर्देशों तथा उसके अंतर्गत संशोधनों को निरसित किया जाता है। बशर्ते यह कि इस तारीख से पूर्व हस्ताक्षर किया गया कोई भी करार या की गई कोई भी कार्रवाई उक्त दिशा-निर्देशों के ऐसे निरसन द्वारा प्रभावित नहीं होगी और इसके अंतर्गत निरसित दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होती रहेंगी।

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 17th January, 2017

Guidelines for Procurement of Electricity for Medium Term from Power Stations set up on Finance, Own and Operate (FOO) basis

No. 23/17/2013-R&R(Vol-V).—Whereas the Central Government is engaged in creating an enabling policy and regulatory environment for the orderly growth of generation of electricity in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003 (the “Act”);

Whereas it is incumbent upon the Central Government, State Governments, Electricity Regulatory Commissions and the distribution licensees to promote competition in the procurement of electricity through competitive and transparent processes;

Whereas the Central Government has, after extensive consultations with various stakeholders and experts, evolved a model contractual framework for procurement of electricity by the distribution licensees from power producers who agree to construct and/or operate power generating stations set up on ‘Finance, Own and Operate’ (“FOO”) basis for medium term power or from Traders/Discoms having back to back arrangements with power producers.

Whereas the Central Government had, therefore issued vide its letter No. [No.23/17/2013-R&R] (Vol-II) dated 29th January 2014, the model documents comprising the Model Request for Qualification (the “MRFQ”) and the Model Request for Proposal (the “MRFP”), and Model Agreement for Procurement of Power (the ‘MAPP’) (collectively, the “**Modal Bidding Documents**”) to be adopted by the distribution licensees for procurement of power from the power producers.

Based on the above, the Government of India had notified the Guidelines vide resolution No. 23/17/2013-R&R (Vol-II) dated 10th February 2014, which were further amended vide resolution dated 20th August, 2015.

Whereas, the Central Government has, vide its letter No. 23/17/2013-R&R (Vol-V) dated 16th January, 2017 issued a single document as the “**Standard Bidding Document**” comprising both the Model Request for Qualification (the “MRFQ”) and the Model Request for Proposal (the “MRFP”), and the Model Agreement for Procurement of Power (the “MAPP”) (collectively, the ‘**Standard Bidding Document**’ and the MAPP are referred to as the “**Model Bidding Documents**”) to be adopted by distribution licensees for procurement of electricity from the power producers/Traders/Discoms through a process of open and transparent competitive bidding through an electronic platform (DEEP e-Bidding Portal) based on offer of the lowest tariff from power generating stations constructed and/or operated on FOO basis. The link for the e-Bidding portal is www.mstcecommerce.com, and is also available on the website of Ministry of Power (www.powermin.nic.in) and PFC Consulting Limited (www.pfcclindia.com).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 63 of the Electricity Act, 2003, the Central Government hereby notifies these guidelines to be known as the ‘Guidelines for Procurement of Electricity for medium term from Power Stations set up on Finance, Own and Operate (FOO) basis (the “**Guidelines**”). These Guidelines shall come into effect from the date of publication in the official gazette subject to the following terms and conditions:

1. The terms and conditions specified in the Model Bidding Documents referred to hereinabove shall, by reference, form part of these Guidelines and shall be treated as such.
2. The application of these Guidelines shall be restricted to projects from which power is procured in accordance with an Agreement for Procurement of Power for a period between one and five years, with a provision for extension of this period upto 25% of the initial contract period or one year whichever is lower, with mutual consent.

3. The tariff determined through the electronic bidding process based on these Guidelines comprising the Model Bidding Documents shall be adopted by the Appropriate Commission in pursuance of the provisions of section 63 of the Act.
4. Any deviation from the Model Bidding Documents shall be made by the Distribution Licensees only with the prior approval of the Appropriate Commission. Provided, however, that any project specific modifications expressly permitted in the Model Bidding Documents shall not be construed as deviations from the Model Bidding Documents.
5. The amendments made in the Guidelines for Procurement of Electricity from Thermal Power Stations set up on Design, Build, Finance, Own and Operate (DBFOO) basis vide Ministry of Power Resolution No. 23/9/2015-R&R dated 16th April 2015 in view of new coal block auction policy, shall also apply, *mutatis mutandis*, for procurement of electricity for Medium Term from Power Stations set up on Finance, Own and Operate (FOO) basis.

The 'Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees' issued on 10th February, 2014, as amended on 20th August 2015, including the Model Bidding Documents issued on 29th January 2014 and the amendment thereof are hereby repealed. Provided, however, that any agreements signed or actions taken prior to the date hereof shall not be affected by such repeal of the said guidelines and shall continue to be governed by the guidelines repealed hereunder.

JYOTI ARORA, Jt. Secy.